DHYEYA IAS
most trusted since 2003

DAILY prePARE
Current affairs summary for prelims

23 November 2024

चेन्नई–व्लादिवोस्तोक समुद्री गलियारा :

सन्दर्भ: हाल ही में केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने पूर्वी समुद्री गलियारे (ईएमसी) के शुभारंभ की घोषणा की, जिसके परिणामस्वरूप भारतीय और रूसी बंदरगाहों के बीच माल की आवाजाही के लिए परिवहन समय और दूरी में कमी आएगी, जिससे नए व्यापार अवसर उत्पन्न होंगे।

- चेन्नई-व्लादिवोस्तोक समुद्री गलियारा, भारत और रूस के बीच समुद्री व्यापार को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

मुख्य विशेषताएं और लाभ:

- **दूरी और अवधि:** चेन्नई-व्लादिवोस्तोक समुद्री मार्ग लगभग 5,600 समुद्री मील की दूरी तय करता है, जो मुंबई से रूस के सेंट पीटर्सबर्ग तक के वर्तमान व्यापार मार्ग की 8,675 समुद्री मील की दूरी को काफी कम करता है।
  - » इस नए कारिडोर से परिवहन समय में लगभग 16 दिन की कमी आएगी, जिससे परिवहन समय 40 दिनों से घटकर 24 दिन रह जाएगा। 20-25 नॉट की गति से चलने वाला एक कंटेनर जहाज इस मार्ग को लगभग 10 से 12 दिनों में पूरा कर सकता है।

कार्गो और व्यापार प्रभाव: कच्चे तेल, धातु और वस्त्रें सहित विभिन्न प्रकार के सामान ले जाने वाले कंटेनर जहाज पहले ही भारतीय बंदरगाहों पर पहुंचने लगे हैं, जो गलियारे की परिचालन सफलता का संकेत है। यह व्यापार मार्ग भारत और रूस के बीच द्विपक्षीय व्यापार में सहयोग और वृद्धि के लिए अपार संभावनाएं प्रस्तुत करता है।

पूर्वी समुद्री गलियारे (ईएमसी) का महत्व:

- **रसद लागत में कमी:** परिवहन समय और दूरी में कमी से रसद लागत में लगभग 40% की कमी आएगी, जिससे व्यापार में दक्षता में सुधार होगा और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा।
  - » मुंबई और सेंट पीटर्सबर्ग के बीच स्वेज नहर के माध्यम से वर्तमान व्यापार मार्ग लगभग 40 दिन का है, जो 16,066 किलोमीटर की दूरी तय करता है, जो नए मार्ग के समय और लागत लाभ को दर्शाता है।

भारत के समुद्री क्षेत्र को बढ़ावा:

» भारत का समुद्री क्षेत्र, जो मात्र की दृष्टि से देश के 95% व्यापार तथा मूल्य की दृष्टि से 70% व्यापार को संभालता है, इस नए गलियारे से लाभान्वित होगा।

» यह भारत के समुद्री विजन 2030 के अनुरूप है, जिसमें समुद्री क्षेत्र के विस्तार के उद्देश्य से 150 से अधिक पहल शामिल हैं।

सामरिक भू-राजनीतिक लाभ:

» यह गलियारा रूस के संसाधानों तक बेहतर पहुंच प्रदान करके और प्रशांत व्यापार नेटवर्क में भारत को एक प्रमुख देश के रूप में स्थापित करके भारत की "एक्ट फार ईस्ट" नीति का पूरक है।

» यह मार्ग जापान सागर, दक्षिण चीन सागर और मलक्का जलडमरूमध्य जैसे प्रमुख क्षेत्रें से होकर गुजरता है, जो वैश्विक व्यापार और रणनीतिक समुद्री मार्गों के लिए महत्वपूर्ण हैं।

इसके अतिरिक्त, यह गलियारा दक्षिण चीन सागर में चीन के प्रभुत्व को भी संबोधित करता है, जो भू-राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्र है।

वैश्विक संपर्क में वृद्धि हेतु अन्य गलियारे:

» चेन्नई-व्लादिवोस्तोक कॉरिडोर वैश्विक संपर्क बढ़ाने के लिए बनाई गई कई पहलों में से एक है। 2023 के जी20 शिखर सम्मेलन के दौरान घोषित भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारे (IMEEC) और रूस के बाल्टिक तट को भारत के पश्चिमी बंदरगाहों से जोड़ने वाले अंतर्राष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारे (INSTC) में भारत की भागीदारी, क्षेत्रों में अपने समुद्री और व्यापार नेटवर्क को मजबूत करने के लिए भारत की बढ़ती प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

» चेन्नई-व्लादिवोस्तोक समुद्री गलियारा भारत-रूस व्यापार संबंधों में एक महत्वपूर्ण विकास है, जोकि कम रसद लागत एवं बढ़े हुए भू-राजनी. तिक प्रभाव तक के लाभ प्रदान करता है, साथ ही भारत की व्यापक समुद्री रणनीति और वैश्विक आर्थिक एकीकरण में भी योगदान करता है ।

Face to Face Centres
DELHI MUKHERJEE NAGAR: 9205274741, 42 | LAXMI NAGAR : 9205212500, 9205962002 | RAJENDRA NAGAR: 9205274743 | UTTAR PRADESH PRAYAGRAJ: 0532-2260189, 8853467068 | LUCKNOW (ALIGANJ): 0522-4025825, 9506256789 | LUCKNOW (GOMTI NAGAR): 7234000501, 7234000502 | GREATER NOIDA: 9205336037, 38 | KANPUR: 7887003962, 7897003962 | GORAKHPUR : 7080847474, 9161947474 | ODISHA BHUBANESWAR: 9818244644/7656949029
dhyeyaias.com

DHYEYA IAS
most trusted since 2003

DAILY prePARE
Current affairs summary for prelims

23 November 2024

एचआईवी का शीघ्र पता लगाने की तकनीक

सन्दर्भ: हाल ही में जवाहरलाल नेहरू उन्नत वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र (जेएनसीएएसआर), भारत के वैज्ञानिकों ने एड्स वायरस एचआईवी-1 के शीघ्र और सटीक पहचान के लिए एक अभिनव नैदानिक मंच (diagnostic platform) विकसित किया है। इसे जीक्यू टोपोलॉजी-लक्षित विश्वसनीय अनुरूपण बहुरूपता (GQ Topology&targeted Reliable Conformational Polymorphism & GQ&RCP) कहा जाता है।

- यह मंच एचआईवी जीनोम में पाए जाने वाले विशेष चार-स्ट्रैंड डीएनए संरचनाओं, जिन्हें जी-क्वाड्रप्लेक्स (G&Quadrupleñ & GQ) कहा जाता है, को लक्षित करता है। यह खोज एचआईवी की सटीक जांच को सरल और प्रभावी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।

एचआईवी का पता लगाने में वर्तमान सीमाएँ:

» मौजूदा नैदानिक विधियाँ जैसे एलिसा (Enzyme&Linked Immunosorbent Assay & ELISA) और पीसीआर (Polymerase Chain Reaction & PCR) विभिन्न चुनौतियों का सामना कर रही हैं, जो एचआईवी का शीघ्र और सटीक निदान करने में बाधा उत्पन्न करती हैं।

शुरुआती संक्रमणों का पता न लगना: वर्तमान परीक्षण एचआईवी संक्रमण के प्रारंभिक चरण में इसे पहचानने में विफल हो जाते हैं, जो समय पर उपचार की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है।

गलत सकारात्मक परिणाम: कई मौजूदा परीक्षणों में एचआईवी के अलावा अन्य प्रोटीन या एंटीबॉडी के साथ प्रतिक्रिया (क्रॉस-रिएक्टिवि. टी) के कारण गलत सकारात्मक परिणाम देखने को मिलते हैं। इससे मरीज को अनावश्यक मानसिक तनाव झेलना पड़ता है और गलत उपचार का खतरा भी उत्पन्न होता है।

धीमी प्रक्रिया: पारंपरिक परीक्षणों में अक्सर पर्याप्त संवेदनशीलता नहीं होती, जिससे संक्रमण के सूक्ष्म स्तर का पता लगाना मुश्किल हो जाता है। साथ ही, इन परीक्षणों में परिणाम प्राप्त करने में अधिक समय लगता है, जो त्वरित और प्रभावी निदान को बाधित करता है।

ये सीमाएँ एचआईवी जैसी गंभीर बीमारी के निदान में सुधार की आवश्यकता को रेखांकित करती हैं।

एचआईवी का पता लगाने में जी-क्वाड्रप्लेक्स की भूमिका

» जी-क्वाड्रप्लेक्स (GQ) संरचनाएं दुर्लभ चार-स्ट्रैंडेड डीएनए संरचनाएं हैं, जो एचआईवी जीनोम के विशिष्ट क्षेत्रों में पाई जाती हैं।

» GQ संरचनाओं को लक्षित करने से एचआईवी का अधिक चयनात्मक और सटीक पता लगाया जा सकता है। यह झूठे सकारात्मक परिणामों की घटनाओं को कम करने और पारंपरिक तरीकों की सीमाओं को दूर करने में मदद करता है।

जीक्यू-आरसीपी प्लेटफॉर्म कैसे काम करता है?

यह प्लेटफॉर्म एचआईवी जीनोम के 176-न्यूक्लियोटाइड भाग को रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन और प्रवर्धन के माध्यम से पहचानता है।

» पीएच-मध्यस्थ प्रक्रिया डबल-स्ट्रैंडेड डीएनए को जीक्यू संरचना में परिवर्तित करती है। इसे एकल-चरणीय मात्रात्मक प्रक्रिया में आसानी से पता लगाया जाता है।

बेंजोबिस्थियाजोल-आधारित फ्लोरोसेंट जांच (TGS64) विशेष रूप से GQ संरचना से जुड़ती है, जिससे उच्च चयनात्मकता और सटीकता सुनिश्चित होती है।

प्लेटफार्म के लाभ :

» **बढ़ी हुई संवेदनशीलता और सटीकता:** फ्लोरोमेट्रिक डिटेक्शन विधि संवेदनशीलता को बढ़ाती है, जिससे एचआईवी डीएनए के निम्न स्तर का पता लगाना संभव होता है। यह प्रारंभिक चरण में एचआईवी की पहचान के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है।

» **संख्याओं में कमी:** जी-क्वाड्रप्लेक्स की अद्वितीय संरचना को लक्षित करने से पारंपरिक परीक्षणों में देखी जाने वाली क्रॉस-रिएक्टिविटी और झूठी सकारात्मकता की घटनाएं काफी हद तक कम हो जाती हैं।

» **त्वरित परीक्षण:** जीक्यू-आरसीपी प्लेटफॉर्म की एक-चरणीय प्रक्रिया पारंपरिक तरीकों की तुलना में समग्र परीक्षण समय को कम करती है, जिससे तेज और कुशल परिणाम मिलते हैं।

» **बहुपयोगी :** मूल रूप से SARS-CoV-2 के लिए डिजाइन किया गया यह प्लेटफॉर्म, एचआईवी के लिए अनुकूलनीय है। इसका उपयोग अन्य डीएनए/आरएनए आधारित रोगजनकों, जैसे बैक्टीरिया और वायरस, का पता लगाने के लिए भी किया जा सकता है।

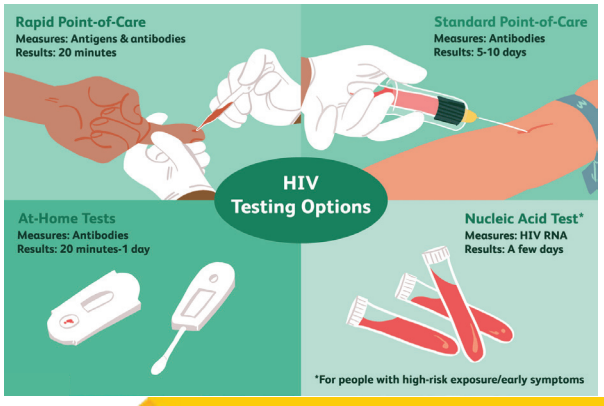

Face to Face Centres
DELHI MUKHERJEE NAGAR: 9205274741, 42 | LAXMI NAGAR : 9205212500, 9205962002 | RAJENDRA NAGAR: 9205274743 | UTTAR PRADESH PRAYAGRAJ: 0532-2260189, 8853467068 | LUCKNOW (ALIGANJ): 0522-4025825, 9506256789 | LUCKNOW (GOMTI NAGAR): 7234000501, 7234000502 | GREATER NOIDA: 9205336037, 38 | KANPUR: 7887003962, 7897003962 | GORAKHPUR : 7080847474, 9161947474 | ODISHA BHUBANESWAR: 9818244644/7656949029
dhyeyaias.com

DHYEYA IAS
most trusted since 2003

DAILY prePARE
Current affairs summary for prelims

23 November 2024

व्यापक अनुप्रयोग की संभावना:

» यह प्लेटफॉर्म डीएनए और आरएनए आधारित रोगजनकों का पता लगाने की क्षमता रखता है।
» इसकी बहुमुखी कार्यक्षमता एचआईवी के साथ-साथ अन्य संक्रामक रोगों के त्वरित और विश्वसनीय निदान के लिए इसे एक प्रभावी उपकरण बनाती है।
» यह तकनीक नैदानिक प्रक्रियाओं में सुधार कर, वायरल और बैक्टीरियल रोगजनकों के लिए तेज, सटीक और किफायती परीक्षण प्रदान करने में सहायक हो सकती है।

लीडआईटी का वार्षिक शिखर सम्मेल

सन्दर्भ: हाल ही में लीडआईटी (उद्योग परिवर्तन के लिए नेतृत्व समूह) के वार्षिक शिखर सम्मेलन की सह-अध्यक्षता भारत और स्वीडन ने बाकू, अजरबैजान में जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (यूएनएफसीसीसी) के COP29 के दौरान की।

» शिखर सम्मेलन में देशों और कंपनियों को औद्योगिक क्षेत्रों के कम कार्बन उत्सर्जन के लिए रणनीतियों पर चर्चा करने के लिए एक साथ लाया गया, जिन्हें पेरिस समझौते के जलवायु लक्ष्यों के साथ संरेखित किया गया।

लीडआईटी के बारे में:

» लीडआईटी एक वैश्विक पहल है जो ऊर्जा-गहन उद्योगों, जैसे कि स्टील, सीमेंट, रसायन, विमानन और शिपिंग को कम कार्बन उत्सर्जन वाले मार्गों पर बदलने में तेजी लाने पर केंद्रित है। ये क्षेत्र कार्बन मुक्त बनाने के लिए सबसे कठिन माने जाते हैं और वैश्विक कार्बन उत्सर्जन में महत्वपूर्ण योगदान करते हैं।

» लीडआईटी का उद्देश्य देशों, उद्योगों और हितधारकों के बीच सहयोगात्मक प्रयासों को उत्प्रेरित करना है ताकि इन क्षेत्रों को 2050 तक शुद्ध-शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने में मदद मिल सके।

लॉन्च और समर्थन:

» लीडआईटी को 2019 में स्वीडन और भारत की सरकारों द्वारा संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन में लॉन्च किया गया था। यह विश्व आर्थिक मंच द्वारा समर्थित है और औद्योगिक डीकार्बोनाइजेशन की चुनौतियों का समाधान करने में सरकारों और उद्योगों को शामिल करता है।

मुख्य लक्ष्य:

» लीडआईटी का मुख्य लक्ष्य जलवायु परिवर्तन को कम करने और संधारणीय औद्योगिक प्रथाओं को आगे बढ़ाने के लिए पेरिस समझौते के साथ अपनी औद्योगिक रणनीतियों को संरेखित करने के लिए प्रतिबद्ध देशों और कंपनियों को एक साथ लाना है।
» 2023 में COP28 में लीडआईटी 2.0 के दौरान शुरू की गई भारत-स्वीडन उद्योग संक्रमण साझेदारी को अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, हरित प्रौद्योगिकियों के सह-विकास और भारी उद्योगों में कम कार्बन उत्सर्जन को आगे बढ़ाने के लिए ज्ञान साझा करने के लिए एक मॉडल के रूप में मान्यता दी गई थी।

व्यापक अनुप्रयोग की संभावना:

» शिखर सम्मेलन का समापन वैश्विक समुदाय से कम कार्बन वाले औद्योगिक भविष्य के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को मजबूत करने के आह्वान के साथ हुआ, जिसमें इस बात पर जोर दिया गया कि यह प्रयास न केवल जलवायु लक्ष्यों का समर्थन करता है, बल्कि आर्थिक अवसर, रोजगार और लचीले समुदाय भी उत्पन्न करता है।

भारत ने अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से औद्योगिक परिवर्तन एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई, यह मानते हुए कि सहयोगात्मक वैश्विक कार्रवाई सभी के लिए एक संधारणीय और समृद्ध भविष्य की ओर ले जाएगी।

भारत-कैरिकॉम संबंध

सन्दर्भ: हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जॉर्जटाउन, गुयाना में आयोजित दूसरे भारत-कैरिकॉम शिखर सम्मेलन के दौरान भारत और कैरेबियाई समुदाय (कैरिकॉम) के बीच साझेदारी को सुदृढ़ करने के लिए सात प्रमुख स्तंभों का प्रस्ताव रखा।

» यह शिखर सम्मेलन, जो 50 वर्षों में किसी भारतीय राष्ट्राध्यक्ष की गुयाना की पहली यात्रा थी, व्यापार, प्रौद्योगिकी, पर्यटन, स्वास्थ्य और कृषि जैसे प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देने पर केंद्रित था।

भारत-कैरिकॉम साझेदारी के बारे में :

» कैरिकॉम 15 कैरेबियाई देशों का एक क्षेत्रीय संगठन है, जो विभिन्न क्षेत्रों में आर्थिक एकीकरण और सहयोग को बढ़ावा देता है।

» पहला भारत-कैरिकॉम शिखर सम्मेलन 2003 में हुआ था, जिसने सहयोग के लिए मंच तैयार किया और 2024 में दूसरा शिखर सम्मेलन द्विपक्षीय जुड़ाव में एक उन्नत चरण को चिह्नित करता है।

Face to Face Centres
DELHI MUKHERJEE NAGAR: 9205274741, 42 | LAXMI NAGAR : 9205212500, 9205962002 | RAJENDRA NAGAR: 9205274743 | UTTAR PRADESH PRAYAGRAJ: 0532-2260189, 8853467068 | LUCKNOW (ALIGANJ): 0522-4025825, 9506256789 | LUCKNOW (GOMTI NAGAR): 7234000501, 7234000502 | GREATER NOIDA: 9205336037, 38 | KANPUR: 7887003962, 7897003962 | GORAKHPUR : 7080847474, 9161947474 | ODISHA BHUBANESWAR: 9818244644/7656949029
dhyeyaias.com

DHYEYA IAS
most trusted since 2003

DAILY prePARE
Current affairs summary for prelims

23 November 2024

प्रधानमंत्री मोदी के सात प्रमुख स्तभंः

» **व्यापारः** मोदी ने भारत और कैरिबियन के बीच व्यापार संबंधों को गहरा करने और एक मजबूत व्यापार पारिस्थितिकी तंत्र बनाने, बाधाओं को कम करने और नए व्यापार मार्ग खोलने पर जोर दिया।

» **प्रौद्योगिकीः** आईसीटी, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और डिजिटल बुनियादी ढांचे में भारत के नेतृत्व का लाभ उठाते हुए, मोदी ने कैरिकॉम देशों में डिजिटल परिवर्तन को बढ़ावा देने के लिए भारत के तकनीकी संसाधनों का उपयोग करने का प्रस्ताव रखा।

» **पर्यटनः** कैरिबियन के लिए पर्यटन एक महत्वपूर्ण आर्थिक क्षेत्र है, मोदी ने भारत के बढ़ते यात्रा बाजार को बढ़ावा देने और कनेक्टिविटी में सुधार करने सहित पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए तालमेल को बढ़ावा देने का सुझाव दिया।

» **प्रतिभाः** मोदी ने दोनों क्षेत्रों के बीच कौशल और प्रतिभा के आदान-प्रदान का प्रस्ताव रखा, जिससे शैक्षिक आदान-प्रदान, व्यावसा. यिक प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रमों की सुविधा मिल सके।

» **परंपराः** कैरिबियन में भारतीयों के प्रवास के कारण गहरे सांस्कृतिक संबंधों को पहचानते हुए, मोदी ने पारंपरिक बंधनों को मजबूत करने के लिए सांस्कृतिक आदान-प्रदान को बढ़ाने का आह्वान किया।

» **लघु एवं मध्यम उद्यम (एसएमई):** मोदी ने उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए पिछली भारत-कैरिकॉम बैठक से मिले 1 मिलियन डॉलर के अनुदान के आधार पर एसएमई सहयोग के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल बनाने का प्रस्ताव रखा।

» **कृषि और खाद्य सुरक्षाः** कृषि में भारत की प्रगति पर प्रकाश डालते हुए, मोदी ने ज्ञान के आदान-प्रदान और कृषि प्रौद्योगिकी के माध्यम से कैरिबियन में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सहयोग पर जोर दिया।

भारत-कैरिकॉम शिखर सम्मेलन का महत्व :

इस शिखर सम्मेलन ने कैरिबियन के रणनीतिक महत्व के प्रति भारत की बढ़ती मान्यता को प्रदर्शित किया। प्रमुख लाभों में शामिल हैं:

» **आर्थिक सहयोगः** व्यापार, प्रौद्योगिकी और एसएमई संबंधों को मजबूत करने से भारतीय उत्पादों के लिए नए बाजार खुलते हैं और निवेश को बढ़ावा मिलता है।

» **स्वास्थ्य और फार्मास्यूटिकल्सः** किफायती स्वास्थ्य सेवा और टीकों में भारत की विशेषज्ञता कैरिबियन की स्वास्थ्य आवश्यकताओं को पूरा कर सकती है।

» **अक्षय ऊर्जाः** भारत की 150 मिलियन अमेरिकी डॉलर की क्रेडिट लाइन के माध्यम से सतत ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन पर सहयोग जारी रहेगा।

» **आपदा प्रबंधनः** मानवीय सहायता और आपदा राहत में भारत की विशेषज्ञता कैरिकॉम देशों के लिए महत्वपूर्ण है, जैसा कि कोविड-19 महामारी के दौरान देखा गया है।

» **सांस्कृतिक एवं शैक्षिक आदान-प्रदानः** आदान-प्रदान बढ़ने से लोगों के बीच संबंध मजबूत होंगे तथा आपसी समझ को बढ़ावा मिलेगा।

पॉवर पैक्ड न्यूज

भारत का पहला एआई डेटा बैंक लॉन्च

हाल ही में, भारत ने अपना पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) डेटा बैंक लॉन्च किया है, जो नवाचार को बढ़ावा देने और राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस पहल का अनावरण केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री ने ASSOCHAM AI लीडरशिप मीट 2024 के 7वें संस्करण के दौरान किया।

- **AI डेटा बैंक शोधकर्ताओं, स्टार्टअप्स और डेवलपर्स को उच्च-गुणवत्ता वाले और विविध डेटासेट तक पहुंच प्रदान करेगा, जो स्केलेबल और समावेशी AI समाधानों को बनाने के लिए आवश्यक हैं।**
- **इस कार्यक्रम में "भारत के लिए AI: भारत के AI विकास को आगे बढ़ाना - नवाचार, नैतिकता और शासन" थीम पर AI की परिवर्तनकारी क्षमताओं का लाभ उठाने के लिए भारत की रणनीतिक योजना पर प्रकाश डाला गया।**
- **AI डेटा बैंक की एक प्रमुख विशेषता उपग्रह, ड्रोन और IoT डेटा के वास्तविक समय के विश्लेषण को सक्षम करना है, जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा को बढ़ाने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका सुनिश्चित होती है। यह पहल आपदा प्रबंधन में पूर्वानुमान विश्लेषण के लिए AI के उपयोग और साइबर सुरक्षा को मजबूत करने के भारत के व्यापक लक्ष्यों के अनुरूप है।**

Face to Face Centres
DELHI MUKHERJEE NAGAR: 9205274741, 42 | LAXMI NAGAR : 9205212500, 9205962002 | RAJENDRA NAGAR: 9205274743 | UTTAR PRADESH PRAYAGRAJ: 0532-2260189, 8853467068 | LUCKNOW (ALIGANJ): 0522-4025825, 9506256789 | LUCKNOW (GOMTI NAGAR): 7234000501, 7234000502 | GREATER NOIDA: 9205336037, 38 | KANPUR: 7887003962, 7897003962 | GORAKHPUR : 7080847474, 9161947474 | ODISHA BHUBANESWAR: 9818244644/7656949029
dhyeyaias.com

DHYEYA IAS
most trusted since 2003

DAILY prePARE
Current affairs summary for prelims

23 November 2024

के संजय मूर्ति ने भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के रूप में शपथ ल

- हाल ही में के संजय मूर्ति को भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) के रूप में नियुक्त किया गया है। उन्होंने राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा प्रशासित पद की शपथ ली। वे गिरीश चंद्र मुर्मू की जगह लेंगे, जिन्होंने अगस्त 2020 से CAG के रूप में कार्य किया। इस भूमिका से पहले, संजय मूर्ति शिक्षा मंत्रालय में उच्च शिक्षा विभाग के सचिव थे।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) के बारे में

- CAG का पद भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 के तहत स्थापित किया गया है।
- CAG भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग का नेतृत्व करता है और केंद्र तथा राज्य दोनों स्तरों पर उचित वित्तीय प्रबंधन सुनिश्चित करता है।
- इसे सार्वजनिक धन के संरक्षक के रूप में जाना जाता हैं और यह देश की वित्तीय प्रणाली की निगरानी करता है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि यह संविधान और संसद द्वारा बनाए गए कानूनों के अनुरूप हो।
- CAG भारत के लोकतंत्र में एक प्रमुख व्यक्ति है, जो वित्तीय मामलों में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए काम करता है। इससे शासन को मजबूत बनाने और राष्ट्रीय संसाधनों के प्रबंधन में जनता का विश्वास बनाने में मदद मिलती है

अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में 104वें सदस्य के रूप में शामिल हुआ आर्मेनिया

- आर्मेनिया अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (आईएसए) का 104वां पूर्ण सदस्य बन गया है, जिसने सौर ऊर्जा को आगे बढ़ाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता को मजबूत किया है।
- आर्मेनियाई राजदूत वहगन अफयान और विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव अभिषेक सिंह के बीच औपचारिक प्रक्रियायें पूरी की गयी।

अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के बारे में:

- आईएसए, एक संधि-आधारित अंतर्राष्ट्रीय अंतर-सरकारी संगठन है। इसका मुख्यालय भारत में है, जिसका लक्ष्य सौर ऊर्जा की सुविधा के लिए 2030 तक 1,000 बिलियन अमरीकी डालर से अधिक का निवेश जुटाना है।

Face to Face Centres
DELHI MUKHERJEE NAGAR: 9205274741, 42 | LAXMI NAGAR : 9205212500, 9205962002 | RAJENDRA NAGAR: 9205274743 | UTTAR PRADESH PRAYAGRAJ: 0532-2260189, 8853467068 | LUCKNOW (ALIGANJ): 0522-4025825, 9506256789 | LUCKNOW (GOMTI NAGAR): 7234000501, 7234000502 | GREATER NOIDA: 9205336037, 38 | KANPUR: 7887003962, 7897003962 | GORAKHPUR : 7080847474, 9161947474 | ODISHA BHUBANESWAR: 9818244644/7656949029
dhyeyaias.com